



*CW*

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 1992/वैशाख 31, 1914

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1992/VAISAKHA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी काटी हुई जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वस्त्र नियालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

विषय:— केसेक्टर वर्ष 1992-93 के लिए उन देशों को परिवासों तथा  
नियालय के सम्बन्ध में ओ जो एल-3 के अन्तर्गत नियाल संबंधी  
मार्गदर्शी सिद्धात जिन देशों में इस प्रकार के नियाल को मात्रा-  
प्रतिक्रियों के सहत कवर किया जाता है।

सं. 1/110/91-ई. पी. (टी. एण्ड जे)-1 (अपरेल) :— उपरोक्त  
विषय पर दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई. पी.  
(टी. एण्ड जे)-1 (अपरेल) और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 1/99/90  
ई. पी. (टी. एण्ड जे) 1 (अपरेल) दिनांक 7-8-91, इ 1/4/90-ई. पी. (टी. एण्ड जे)-  
1 (अपरेल) दिनांक 13-11-91 तथा 1/4/90-ई. पी. (टी. एण्ड जे)-  
1 (अपरेल) दिनांक 11-12-1991 की ओर छान आकर्ति किया जाता  
है। यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना  
सं. 1/4/90-ई. पी. (टी. एण्ड जे) (अपरेल) में निम्नोक्त घनुसार संशोधन  
किया जाए :

2. पैरा 16 में एक नया उप-पैरा (iv) जैसा दिया जाएगा जो इस  
प्रकार पढ़ा जाए :

16 (iv) (क) उन नियालों को जिनको आधार प्रवाहि के बीच  
उनके नियाल नियालन के आवार पर संबंधित अवैदन  
वर्ष के लिये 25,000 प्रश्न में अवधित विना नियालन  
हकदारी का आवैदन किया गया हो। जिनमें सभी देशों/  
प्रजातों को नियाल शामिल है वे एम शी/बी जो के स्थान  
पर निम्नलिखित शर्तों पर वैध आवासन (एल यू टी)  
देने का विकल्प होगा :—

(क) एम शी/बी जो के स्थान पर वैध आवासन  
देने की सुविधा विना नियालन हकदारी, गैर-  
कोटा हकदारी, विनिर्मान नियाल विना हकदारी और  
सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी योजनाओं के प्रत्यक्षीत  
पात्र नियालों की हकदारियों के विस्तार/  
पुरा वैधन में लागू होंगी। यह सुविधा  
पड़ते याओं, पहने पात्रों योजना में साबदनों  
या विस्तार के लिये उपयोग नहीं होगी।  
यह सुविधा गैर-कोटा हकदारी योजना प्रवाह  
विना नियालन के अंतरा द्वारा प्राप्त हकदारियों  
के विस्तार/गुनः वैधता में भी लागू नहीं होगी।

(ख) यदि वैध आवासन में शामिल की गई हकदारियों  
के संबंध में जात की गई किसी धनराशि के

लिये नियंत्रित हकदारी विवरण नोटि के प्रत्युत्साह महानिदेशक, अपैरल नियंत्रित सर्वधन परिषद् दावा करता है तो सबधित नियंत्रित को जिसने ऐसा आवश्यकन दिया है, महानिदेशक, अपैरल नियंत्रित सर्वधन परिषद् द्वारा किए गए ऐसे दावे की तिथि से 90 दिनों की श्रविधि के भीतर दावा की गई ऐसी राशियों का भुगतान करना होगा। यदि ऐसा करने में वह असफल होता है तो नियंत्रित लदान का किसी भी प्रकार दावा प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, किंतु जी योजना में हाज़ारों या के न्यूनतम ग्रन्ति इस द्वीपों के लिए नियंत्रित द्वारा ने

(i) यदि योजना के लिए उत्तम विकास के लिए जी योजना के न्यूनतम ग्रन्ति के लिए जी योजना के लिए जी के स्थान पर वध आवश्यक दन की सुविधा को बाप्स ले सकता है।

(ii) इस द्वीपों के स्थान पर वध आवश्यक परिवर्तन सहित वध आवश्यक पर भी लागू होंगे।

3. मोजूदा परा 16 (iv) से 16 (vii) की सध्या में परिवर्तन करके 16 (v) से 16 (viii) कर दिया जाएगा।

4. समय-समय पर संशोधित दिनांक 31-8-90 की श्रधिसूचना स. 1/4/90-ई पी (टी एण्ड जे) -1 (अपैरल) की अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

एस नारायणन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1992

**Subject :** Guidelines for Export Under OGL-3 in respect of garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar years 1991-93.

No. 1/110/91-EP(T&J)—I (Apparel).—Attention is invited to Notification No. 1/4/90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 31-8-90 on the above mentioned subject and subsequently amended vide Notification No. 1/99/90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 7th August 91; 1/4/90-EP(T&J)-I dated 13th November 1991 and 1/4/90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 11-12-1991. It has

been decided to amend the Notification No. 1/4/90-EP (T&J)I (Apparel) dated 31-8-90 as follows :

2. In Para 16, a new sub-para (iv) shall be inserted which reads :

'16 IV. Exporters who have been allotted Past Performance Entitlements of not less than 25,000 pcs. for the respective allotment year on the basis of their export performance during the base period, for all country categories taken together, will have an option of submitting a Legal Undertaking ("UT") in place of EMD/BG, subject to the following conditions—

(a) The facility of submitting LUT in place of EMD/BG will apply to extension/re-validation of entitlements of eligible exporters in FPE, NQE, MEE and PSE systems. In FCFS system, this facility will not be available either for allotments or for extension. The facility will also not apply to extension/re-validation of entitlements obtained by transfer in Past Performance or Non-Quota Entitlement systems.

(b) If DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter/concern which had submitted the Legal Undertaking would remit the amounts so claimed by DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim, failing which the exporter will not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of entitlements or return of EMD/BGS in any systems until the amounts are remitted and DG, AEPC decides to re-instate these facilities for the exporter.

(c) DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD/BG for any exporters who are otherwise eligible for the facility, but have failed to remit any forfeiture amounts within the stipulated period of 90 days.

(d) The guidelines and stipulations applicable to EMD/BG will also apply to LUT, mutatis mutandis.

3. The existing paras 16 (iv) to 16 (vii) shall be renumbered to 16 (v) to 16 (viii).

4. All other terms and conditions of Notification No. 1/4/90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 31.8.90 amended from time to time remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.